भारत - जर्मनी संबंध

राजनीतिक संबंध

भारत 1951 में युद्ध पश्चात जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति समाप्त करने वालों और जर्मनी संघीय गणराज्य को मान्यता देने वाले पहले राज्यों में से एक है। लोकतंत्र के साझे मूल्यों तथा कानून के शासन पर आधारित संबंध 1990 में भारत के आर्थिक उदारीकरण तथा शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद काफी सुदृढ़ हुए हैं। पिछले दशक में, भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों तरह की अंत:क्रिया में काफी वृद्धि हुई है। आज, जर्मनी द्विपक्षीय एवं वैश्विक दोनों संदर्भों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है।

द्विपक्षीय संबंध के क्रम को 1956 एवं 1960 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जर्मनी की दो यात्राओं द्वारा स्थापित किया गया। नियमित रूप से द्विपक्षीय आदान - प्रदान होते हैं जिसमें सर्वोच्च स्तर पर होने वाले आदान - प्रदान भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में, दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तर पर नियमित रूप से यात्राएं हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह 2006, 2010 और 2013 में जर्मनी का दौरा किया। हनोवर मेस्से 2015 में साझेदार देश के रूप में भारत की भागीदारी के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 अप्रैल, 2015 के दौरान जर्मनी का अधिकारिक दौरा किया। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 25 – 27 जून, 2015 के दौरान जर्मनी का अधिकारिक दौरा किया। जर्मनी के ओर से, जर्मनी के राष्ट्रपति जोसिम गाउक ने फरवरी, 2014 में भारत का राजकीय दौरा किया। चांसलर एंजिला मर्केल ने 2007, 2011 में भारत का दौरा किया और फिर 4 से 6 अक्टूबर 2015 के दौरान तीसरे अंतर सरकारी परामर्श के लिए भारत का दौरा किया। उनके साथ चार कैबिनेट मंत्री, तीन संसदीय राज्य सचिव और एक उच्च स्तरीय कारोबारी शिष्टमंडल आया था। इस यात्रा के दौरान कुल 18 द्विपक्षीय एम ओ यू एवं करारों पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें सुरक्षा सहयोग, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग करार शामिल हैं।

2001 से भारत और जर्मनी के बीच एक सामरिक साझेदारी है जिसे अंतर सरकारी परामर्श (आई जी सी) के तीन चक्रों के माध्यम से और सुदृढ़ किया गया है। अंतर सरकारी आयोग की पहली बैठक मई 2011 में नई दिल्ली में हुई थी, अंतर सरकारी आयोग की दूसरी बैठक अप्रैल 2013 में बर्लिन में हुई थी और अंतर सरकारी आयोग की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 5 अक्टूबर 2015 को हुई। आपसी रूचि के द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच अनेक संस्थानिक व्यवस्थाएं हैं जैसे कि सामरिक वार्ता, विदेश कार्यालय परामर्श, औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग, उच्च प्रौद्योगिकी साझेदारी समूह, उच्च रक्षा समिति और आतंकवाद की खिलाफत पर संयुक्त कार्य समूह, भारत-जर्मन ऊर्जा मंच, भारत-जर्मन पर्यावरण मंच, भारत - जर्मनी परामर्श समूह आदि। भारत और जर्मनी जी-4 की रूपरेखा के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के मुद्दे पर निकटता से सहयोग करते हैं। दोनों पक्ष विदेश नीति के मुद्दों जैसे कि पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, यू एन मुद्दे, नि:शस्त्रीकरण एवं अप्रसार आदि पर नियमित रूप से परामर्श करते हैं। दोनों पक्षों के बीच पहली नीति आयोजना वार्ता 23 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में हुई है।

दोनों देशों के संसद सदस्यों के बीच नियमित रूप से अंत:क्रियाएं होती हैं। 1971 में, **बुंदेसटाग** (जर्मन संसद) में स्थापित भारत - जर्मनी संसदीय समूह ने दोनों देशों की संसदों के बीच संपर्कों को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। सीडीयू से संसद सदस्य श्री राल्फ ब्रिंखौस की अध्यक्षता में 18वें बुंदेसटाग में एक 16 सदस्यीय भारत - जर्मनी संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है। श्री ब्रिंखौस के नेतृत्व में संसद सदस्यों के एक समूह ने फरवरी 2015 में भारत का दौरा किया। बुंडेसटाग की वाइस प्रेसीडेंट सुश्री क्लौडिया रोथ ने मार्च 2015 में भारत का दौरा किया। दोनों पक्षों के अनेक अन्य संसद सदस्यों ने हाल की अवधि में एक दूसरे के देशों की यात्राएं की हैं।

रक्षा के क्षेत्र में 2006 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया गया जो वार्षिक परामर्श की रूपरेखा प्रदान करता है। रक्षा सचिव के स्तर पर उच्च रक्षा समिति (एच डी सी) की बैठकें हर साल नई दिल्ली एवं बर्लिन में वैकल्पिक तौर पर होती हैं। एच डी सी की 7वीं बैठक का आयोजन जुलाई 2014 में नई दिल्ली में हुआ। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन ने 7 से 10 जुलाई, 2014 के दौरान जर्मनी का आधिकारिक दौरा किया। दोनों पक्षों

ने मई 2015 में जर्मनी की रक्षा मंत्री सुश्री उर्सुला वोन दर लेयन की भारत की हाल की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के साथ बैठक की।

दोनों देशों के कुछ राज्यों एवं शहरों ने आपस में जुड़वा व्यवस्थाएं की हैं। 2007 से कर्नाटक और बावरिया (जर्मनी) के बीच सिस्टर राज्य व्यवस्था है। इसी तरह मुम्बई और स्टुटगार्ट (जर्मनी) 1968 से सिस्टर सिटी हैं। जनवरी 2015 में महाराष्ट्र और बाडेन - वुर्टमबर्ग (जर्मनी) ने सिस्टर राज्य संबंध स्थापित करने के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं।

आर्थिक एवं वाणिजयिक संबंध

भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही चले आ रहे हैं जब ऑगसबर्ग और नुरेमबर्ग से जर्मनी की व्यापार कंपनियों ने अफ्रीका के आसपास एक नए समुद्री मार्ग का विकास किया जब वे बहुमूल्य पत्थरों एवं मसालों की तलाश में समुद्री यात्रा कर रहे थे। इसके पश्चात, 16वीं एवं 18वीं शताब्दियों में भारत तथा एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से अनेक जर्मन कंपनियां स्थापित की गईं। सीमेंस के संस्थापक वर्नर वॉन सिमेंस ने कोलकाता एवं लंदन के बीच टेलीफोन लाइन बिछाए जाने के कार्य का निजी तौर पर पर्यवेक्षण किया था जो 1870 में पूरी हुई थी। एशिया में बायेर की पहली पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी "फारबेनफैब्रिकेन बायेर एंड कं. लि." का गठन 1896 में मुंबई में हुआ था।

पिछले वर्षों में आर्थिक संबंधों में काफी विस्तार हुआ है। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। जर्मनी भारत के शीर्ष 10 वैश्विक व्यापार साझेदारों में लगातार बना हुआ है। तथापि, विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कारकों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार का प्रवाह ठहर गया है। 2014 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15.96 बिलियन यूरो था। जर्मनी के कुल व्यापार में लगभग 1 प्रतिशत की भागीदारी के साथ 2014 के दौरान जर्मनी के वैश्विक व्यापार में भारत 25वें स्थान पर था। जनवरी से अक्टूबर 2015 की अवधि के लिए कुल व्यापार 14.6 मिलियन यूरो था।

गारमेंट एवं टेक्सटाइल उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़े से बने माल, लोहा एवं इस्पात, मेटल गुड्स, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, भेषज उत्पाद तथा आटो कंपोनेंट ऐसे प्रमुख आइटम हैं जिनका भारत से जर्मनी को निर्यात किया जाता है। जर्मनी से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में विद्युत उत्पादन के उपकरण, आटो कंपोनेंट, कंपलीट फेब्रिकेशन प्लांट, बेयरिंग, गियर उपकरण, मीजरमेंट एवं कंट्रोल उपकरण, प्राथमिक रासायनिक उत्पाद, सिंथेटिक सामग्री, मशीन टूल, एयरक्राफ्ट तथा लोहा एवं स्टील शीट आदि शामिल हैं।

वर्ष 2000 से जर्मनी भारत में 8वां सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है। 1991 से जून, 2015 की अवधि के दौरान भारत में जर्मनी से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है उसका मूल्य 8.86 बिलियन अमरीकी डालर आंका गया है। भारत में 2014 में जर्मन एफ डी आई 1.15 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास था। 1600 से अधिक भारत - जर्मनी साझेदारियां तथा 600 से अधिक भारत - जर्मनी संयुक्त उद्यम प्रचालन में हैं। भारत में जर्मनी का निवेश मुख्य रूप से परिवहन, विद्युत उपकरण, मेटलर्जिकल उद्योगों, सेवा क्षेत्र (विशेष रूप से बीमा), रसायन, निर्माण गतिविधि, व्यापार एवं आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में है। जर्मनी की अधिकांश बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार में पहले ही पदार्पण कर चुकी हैं। जर्मनी की आटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे कि डैमलर, वोल्क्सवैगन, बी एम डब्ल्यू, और ऑडी ने भारत में विनिर्माण सुविधाएं / असेंबली प्लांट स्थापित किए हैं। जर्मनी की अन्य प्रमुख कंपनियों जिनका भारत में प्रचालन उल्लेखनीय है, में सीमेंस, थाइसेन क्रुप्प, बोस्क, बेयर, बी ए एस एफ, एस ए पी, ड्यूटसक बैंक, मेट्रो, लुफ्थांसा, मर्क, म्यूनिक रे आदि शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी कंपनियां, जर्मनी मध्यम उद्यम (मिटलस्टैंड) भी भारत में गहरी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत में जर्मन कंपनियों के लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम स्थापित करने के लिए अंतर सरकारी आयोग की तीसरी बैठक के दौरान एक संयुक्त घोषणा की गई।

जर्मनी में अनेक महत्वपूर्ण ट्रेड फेयर का आयोजन होता है जिसमें भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों एवं प्रौद्योगिकी का प्रचार - प्रसार करने के लिए नियमित रूप से भाग लेती हैं। भारत हनोवर मेस्से, 2015 में साझेदार देश था। वर्ष 2001 में स्थापित भारत - जर्मनी गोलमेज (जी आई आर टी) का उद्देश्य भारत के बारे में सूचना का प्रसार करना और भारत - जर्मनी व्यवसाय संबंधों को सुगम बनाना है। जर्मनी में जी आई आर टी के 14 अध्याय हैं जो नियमित 'स्टैमटिस्च' बैठकों के माध्यम से भारत - जर्मनी व्यवसाय के अलावा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के काम में लगे हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी में भारतीय निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। भारतीय कारपोरेट संस्थाओं ने जर्मनी में 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक धनराशि का निवेश किया है। जर्मनी में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां प्रचालन कर रही हैं। आई टी, आटोमोटिव, फार्मा तथा बायोटेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने अधिक निवेश किया है। जर्मन बाजार में भारतीय साफ्टवेयर कंपनियों की पैठ बढ़ रही है तथा इनफोसिस, विप्रो तथा टी सी एस जैसे प्रमुख भारतीय साफ्टवेयर प्रदाताओं ने जर्मनी में अपना प्रचालन शुरू किया है। भारत फोर्ज लिमिटेड, रैनबैक्सी, पिरामल, सामटेल, हेक्सावेयर टेक्नोलाजीज, एन आई आई टी, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, हिंदुजा ग्रुप, डा. रेड्डी लैबोरेटरीज, बायोकान, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, महिंद्रा जैसी कंपिनयों तथा अन्यों ने या तो जर्मन कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है अथवा अपनी स्वयं की सहायक कंपनियां आरंभ की हैं।

भारत - जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की शुरूआत 1971 एवं 1974 में अंतर सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर के साथ हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए जर्मनी भारत के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच 150 से अधिक संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं तथा 70 प्रत्यक्ष साझेदारियां हैं। भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं की जर्मनी की प्रमुख आर एंड डी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ साझेदारी है जिसमें मैक्स प्लांक सोसायटी, फ्राउनहोफर लैबोरेटरीज तथा अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड्ट फाउंडेशन शामिल हैं। प्रत्येक पक्ष से 1 मिलियन यूरो के वार्षिक अंशदान के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित भारत - जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का गठन 2008 में नई दिल्ली में हुआ। प्रत्येक पक्ष द्वारा 4 मिलियन यूरो के वार्षिक अंशदान के साथ अंतर सरकारी आयोग की तीसरी बैठक में इस केन्द्र के कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत ने जर्मनी में प्रमुख विज्ञान परियोजनाओं में निवेश किया है जैसे कि डर्मसटड में एंटी प्रोटन एंड आयन रिसर्च सुविधा तथा उन्नत सामग्री एवं पार्टिकल फिजिक्स में प्रयोग के लिए डच इलेक्ट्रानन सिंक्रोट्रान (डी ई एस वाई)।

जर्मनी कई दशकों से एक महत्वपूर्ण विकास सहयोग साझेदार भी रहा है। 1958 में सहयोग आरंभ होने के बाद से कुल द्विपक्षीय तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की राशि 12 बिलियिन यूरो है। विकास सहयोग के तहत ऊर्जा, संपोषणीय आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं पर्यावरण प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। जर्मनी से वित्तीय सहायता मुख्य रूप से उदार ऋण, संयुक्त ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान की गई है जो के एफ डब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से आती है। तकनीकी सहायता जी आई जेड - जर्मन सरकार की विकास एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाती है। अंतर सरकारी आयोग की तीसरी बैठक में भारत - जर्मनी सौर ऊर्जा साझेदारी के संबंध में विकास सहयोग के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत जर्मनी अगले पांच वर्षों में 1 बिलियन यूरो का रियायती ऋण प्रदान करेगा।

सांस्कृतिक संबंध :

भारत और जर्मनी के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान - प्रदान की एक लंबी परंपरा है। मैक्समूलर भारत - यूरोपीय भाषाओं के पहले विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों एवं ऋगवेद का अनुवाद किया और प्रकाशित किया। भारतीय नृत्य, संगीत तथा साहित्य और विशेष रूप से मोशन पिक्चर एवं टी वी उद्योग, बालीवुड में रूचि बढ़ रही है। न केवल प्रतिष्ठित बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपितु पूरे जर्मनी में अन्य महोत्सवों में भी भारतीय फिल्मों एवं कलाकारों की नियमित रूप से भागीदारी होती है। यहां बालीवुड फिल्मों को नियमित रूप से रिलीज

किया जाता है तथा टेलीविजन के नेटवर्कों पर डब किए गए वर्जन का प्रसारण किया जाता है। जर्मनी में भारतीय पकवान बहुत लोकप्रिय हैं। चांसलर मर्केल ने सद्भाव के प्रदर्शन के रूप में अंतर सरकारी आयोग की तीसरी बैठक में माननीय प्रधानमंत्री को दुर्गा- महिषासुरमर्दनी की चुराई गई मूर्ति को सौंपा।

वर्ष 1994 में बर्लिन में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) द्वारा स्थापित टैगोर केंद्र नृत्य, संगीत, साहित्यिक कार्यक्रम, फिल्म, वार्ता, सेमिनार एवं प्रदर्शनी का बड़े पैमाने पर आयोजन करके भारतीय विरासत एवं इसकी संस्कृति की विविधता को दर्शान के लिए नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबर्ग गेट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। दोनों देशों के लोगों को एक मंच पर लाकर और जर्मनी के लोगों में आधुनिक भारत के बारे में सूचना का प्रसार करके डच - इंडिश गेसेलशाफ्ट (इंडो - जर्मन सोसाइटी) परस्पर सांस्कृतिक सूझबूझ बढ़ाने का काम कर रहा है। जर्मनी में इस सोसायटी की 33 स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनके लगभग 3500 सदस्य हैं जो विभिन्न सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं।

भारतीय दर्शन एवं भाषाओं में जर्मनी की रूचि की वजह से 1818 में बोन विश्वविद्यालय में पहले इंडोलॉजी चेयर का गठन किया गया। भारत सरकार ने जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययनों के अनेक रोटेटिंग चेयर को वित्त पोषित किया है। आज की तिथि तक जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 30 रोटेटिंग चेयर हैं। इसके अलावा, आई सी सी आर जर्मनी में दीर्घ एवं अल्प दोनों अवधि के भारतीय अध्ययन के चेयर की सहायता करता है। 2015 में, आई सी सी आर ने जर्मनी में दो अल्पावधिक चेयर का गठन किया : ह्यूम्बोट विश्वविद्यालय, बर्लिन में और हनोवर के लिबनिज विश्वविद्यालय में। जर्मनी के संस्कृत विद्वान तथा इंडोलोजिस्ट डा. अन्नेट स्मीडशेन को 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

लगभग 12,000 भारतीय छात्र जर्मनी में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 800 के आसपास जर्मन छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं या अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं। भारत के अनेक छात्र जर्मन विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने का विकल्प चुन रहे हैं। जर्मनी की कुछ कंपनियां जर्मन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की भी पेशकश कर रही हैं। जर्मनी शैक्षिक विनिमय सेवा (डी ए ए डी) संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा युवा वैज्ञानिकों / शोध छात्रों के आदान प्रदान को सुगम बनाती है। सहयोग के नए एवं नवाचारी क्षेत्रों के द्वार खोलकर अंतर सरकारी आयोग की तीसरी बैठक में डी ए ए डी और यू जी सी के बीच उच्च शिक्षा में भारत - जर्मनी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष इस प्रयास के लिए 2016 से 2020 तक चार वर्ष की अवधि के लिए 3.5 मिलियन यूरो का वित्त पोषण करेंगे। इसके अलावा, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद घुटने के आस्टियोआर्थराइटिस पर चैरिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी, बर्लिन द्वारा आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान कर रही है, जो यूरोप में आयुर्वेद के प्रयोग के लिए पहला व्यवस्थागत नैदानिक परीक्षण है।

भारतीय समुदाय

जर्मन सरकार के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी में भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या 1,43,000 के आसपास है जिसमें भारतीय एवं जर्मन दोनों पासपोर्ट धारक शामिल हैं। भारतीय डायसपोरा में मुख्य रूप से टेक्नोक्रेट्स, कारोबारी / व्यापारी तथा नर्सें शामिल हैं। कारोबार / सांस्कृतिक मोर्चे पर अनेक भारतीय संगठन और संघ सक्रिय हैं जो जन दर स्तर पर भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को सुदृढ़ कर रहे हैं।

उपयोगी संसाधन :

- भारतीय दूतावास, बर्लिन की वेबसाइट :
  www.indianembassy.de
- भारतीय दूतावास, बर्लिन का फेसबुक पेज :

www.facebook.com/pages/Embassy-of -India-Berlin/147693765304239

*****

जनवरी, 2016